



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक 1939 (श0)

(सं0 पटना 1037) पटना, बुधवार, 8 नवम्बर 2017

सं० 350/बीआरजीएफ(नीति)-17-02/2014/9026-पं०रा०
पंचायती राज विभाग

संकल्प

30 अक्टूबर 2017

विषय : पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों की वित्तीय अधिसीमा की वृद्धि के संबंध में।

राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कई योजनाओं, यथा चौदहवें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गयी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री निश्चय योजना इत्यादि का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9221 दिनांक 19.11.2014 (मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-22.10.2014 में मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृत) के आलोक में विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किया जाता है। उक्त संकल्प द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नवत् किया गया था:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	2	3	4
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रु० तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रु० तक
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख रु० तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	पाँच लाख रु० तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रु० तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रु० तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	दस लाख रु० तक
8	कनीय अभियंता	तकनीकी	पाँच लाख रु० तक

2. विगत वर्षों में योजनागत सामग्रियों एवं श्रम घटकों की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है एवं विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाली राशि से योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत एवं विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों के प्रत्यायोजित शक्तियों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3. अतः पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को निम्नरूपेण प्रत्यायोजित की जाती है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	2	3	4
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रु० तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रु० तक
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रु० तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	पंद्रह लाख रु० तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रु० तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रु० तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रु० तक
8	कनीय अभियंता	तकनीकी	पंद्रह लाख रु० तक

4. उपर्युक्त पूर्व निर्गत संकल्प ज्ञापांक-9221 दिनांक-19.11.2014 में प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम पंचायत, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति की वित्तीय शक्ति की अधिसीमा की वृद्धि की जा रही है। संकल्प के शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश प्रसाद साह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1037-571+200-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>